भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2229

उत्तर देने की तारीख : 12.02.2026

संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में एमएसएमई इकाइयां

2229. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में कितने युवाओं को रोजगार मिला है;

(ग) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(घ) उक्त संघ राज्य क्षेत्र में कितने औद्योगिक सम्पदा और एमएसएमई पार्क विकसित किए गए हैं; और

(ङ) क्या प्रौद्योगिकी उन्नयन और डिजिटल एमएसएमई मिशन के अंतर्गत कोई विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) के अनुसार, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या क्रमशः 21,470 और 13,512 है।

यूआरपी के अनुसार, दिनांक 01.07.2020 को यूआरपी के लॉन्च के बाद से, कुल 7.61 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत किए गए हैं। इन उद्यमों ने दिनांक 31.01.2026 तक 33.52 करोड़ रोजगार की सूचना दी है। आयु-वार डेटा यूआरपी पर नहीं रखा गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत, पिछले 5 वर्षों यानी 2020-21 से 2024-25 तक देश में कुल 4,11,627 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

(घ) : एमएसएमई मंत्रालय देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का कार्यान्वयन करता है। इस योजना के तहत, मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने और नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/(फ्लैटेड) कारखाना परिसरों में अवसंरचना सुविधाओं को स्थापित/उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। एमएसई-सीडीपी एक मांग-संचालित योजना है और सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं। अभी तक दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) : हाल के वर्षों में देश के औद्योगिक परिदृश्य में डिजिटलीकरण में वृद्धि देखी गई है, जिससे एमएसएमई की परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है। मंत्रालय एमएसएमई के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ऑनलाइन उद्यम पंजीकरण, प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्रों में प्रशिक्षण, एमएसएमई नवप्रवर्तन स्कीम के माध्यम से नए विचारों और प्रौद्योगिकियों के इन्क्यूबेशन और हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एमएसई परिवर्तन के लिए हरित निवेश और वित्तपोषण स्कीम (गिफ्ट) स्कीम का समर्थन कर रहा है। ई-कॉमर्स बाज़ार का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए एमएसएमई को डिजिटल उपकरणों और मार्गदर्शन के साथ सशक्त बनाने के लिए, विश्व बैंक समर्थित "एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प)" कार्यक्रम के तहत एमएसएमई टीम (व्यापार सक्षमता और विपणन) को लागू किया जा रहा है।

*****